

स्वच्छता सर्वेक्षण -2021 के तहत शहर के कचरामुक्त स्थलों पर रांगोली निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम निरन्तर जारी

रतलाम । वर्तमान समय में स्वच्छता हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। यह समय रतलाम शहर के लिए बदलाव का समय है, बदलाव के इस दौर में यदि हम स्वच्छता के क्षेत्र में पीछे रह गए तो आर्थिक उन्नति का कोई महत्व नहीं रह जाएगा।

साफ-सफाई केवल कर्मचारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को साफ और सुरक्षित रखें। हमें यह नजरिया बदलना होगा। पुरानी आदतों को बदलने में समय लगेगा लेकिन यह इतना मुश्किल काम भी नहीं है।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार



शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम

से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की ओर से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही

उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आह्वान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर दू डोर कूड़ा होने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है।

स्वच्छता को लेकर नजरिया बदलना होगा

रतलाम । वर्तमान समय में स्वच्छता हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। यह समय रतलाम शहर के लिए बदलाव का समय है, बदलाव के इस दौर में यदि हम स्वच्छता के क्षेत्र में पीछे रह गए तो आर्थिक उन्नति का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। साफ-सफाई केवल कर्मचारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को साफ और सुरक्षित रखें। हमें यह नजरिया बदलना होगा। पुरानी आदतों को बदलने में समय लगेगा लेकिन यह इतना मुश्किल काम भी नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की ओर से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आह्वान लोगों से किया जा रहा है।

समय 10/20/21

कैबिनेट के सामने हुआ जल-जीवन मिशन पर प्रस्तुतिकरण

प्रदेश में 2023 तक जल क्रांति : सीएम

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलेगा घरेलू नल कनेक्शन

भोपाल, (प्रसं)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2023 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रदेश में जल क्रांति होगी। इससे सबसे बड़ी राहत हमारी बहनों को मिलेगी। उन्हें हैंडपंप से मुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा। कुल एक करोड़ 21 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर 44 हजार 260 करोड़ रुपए का व्यय होगा। श्री चौहान मंगलवार को मंत्रालय में जल-जीवन मिशन के प्रस्तुतिकरण के बाद मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जल-जीवन मिशन के संचालन में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और जिस भी ग्राम की परियोजना पूर्ण होगी, वहाँ उसका प्रारंभ उत्सव के रूप में किया जायेगा। गाँव के प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराना ऐतिहासिक उपलब्धि है।



मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित किया।

थर्ड पार्टी निरीक्षण से होगा गुणवत्ता पर नियंत्रण

कैबिनेट के समूह हुए जल-जीवन मिशन के हर घर जल पर प्रस्तुतिकरण में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा की गई थी। मध्यप्रदेश में जून, 2020 से मिशन का क्रियान्वयन आरंभ हुआ। मिशन के क्रियान्वयन के लिए राज्य-स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल और स्वच्छता मिशन तथा राज्य-स्तरीय योजना स्वीकृति समिति विद्यमान है। जिला-स्तरीय समिति में जिला कलेक्टर अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। ग्राम स्तर पर स्व-सहायता समूह के सहयोग से ग्रामवासियों की जन-भागीदारी और योजना के सतत संचालन और संधारण के लिए क्रियान्वयन सहायता संस्था की व्यवस्था है। नल-जल योजनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी की व्यवस्था भी विद्यमान है। जल एवं स्वच्छता समिति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से योजना का निर्माण करेगी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों के बीच सतत समन्वय से अन्य गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

योजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर

वर्ष 2020-21 तक निवाड़ी तथा बुरहानपुर जिलों में शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में भोपाल, दतिया, इंदौर, मुर्ना, नरसिंहपुर, राजगढ़ तथा उमरिया सहित कुल सात जिले पूरी तरह कवर कर लिए जाएंगे। शेष जिले वर्ष 2023 तक पूर्ण कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के 34 हजार 305 गाँवों में सतही स्नोट आधारित समूह योजनाओं से नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेष 16 हजार 382 गाँवों में ट्रेटो फिटिंग द्वारा सुविधा का विस्तार किया जाना है। प्रदेश में 32 लाख 41 हजार परिवारों तक योजना का विस्तार किया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में 25 लाख से अधिक एफएचटीसी के लक्ष्यों वाले राज्यों में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया।

प्रदेश में 2023 तक जल क्रांति - मुख्यमंत्री श्री चौहान

रतलाम 9 फरवरी 2021/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2023 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रदेश में जल क्रांति होगी। इससे सबसे बड़ी राहत हमारी बहनों को मिलेगी। उन्हें हैंडपंप से मुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा। कुल एक करोड़ 21 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर 44 हजार 260 करोड़ रुपए का व्यय होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में जल-जीवन मिशन के प्रस्तुतिकरण के बाद मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल-जीवन मिशन के संचालन में जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और जिस भी ग्राम की परियोजना पूर्ण होगी, वहाँ उसका प्रारंभ उत्सव के रूप में किया जायेगा। गाँव के प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराना ऐतिहासिक उपलब्धि है।

थर्ड पार्टी निरीक्षण से होगा गुणवत्ता पर

नियंत्रण-मंत्रि-परिषद के समूह हुए जल-जीवन मिशन के 'हर घर जल' पर प्रस्तुतिकरण में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा की गई थी। मध्यप्रदेश में जून, 2020 से मिशन का क्रियान्वयन आरंभ हुआ। मिशन के क्रियान्वयन के लिए राज्य-स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल और स्वच्छता मिशन तथा राज्य-स्तरीय योजना स्वीकृति समिति विद्यमान है। जिला-स्तरीय समिति में जिला कलेक्टर अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। ग्राम स्तर पर स्व-सहायता समूह के सहयोग से ग्रामवासियों की जन-भागीदारी और योजना के सतत संचालन और संधारण के लिए क्रियान्वयन सहायता संस्था की व्यवस्था है। नल-जल योजनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी की व्यवस्था भी विद्यमान है। जल एवं स्वच्छता समिति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहयोग से योजना का निर्माण करेगी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल विकास और पंचायत एवं ग्रामीण

विकास विभागों के बीच सतत समन्वय से अन्य गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

योजना क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर-वर्ष 2020-21 तक निवाड़ी तथा बुरहानपुर जिलों में शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में भोपाल, दतिया, इंदौर, मुर्ना, नरसिंहपुर, राजगढ़ तथा उमरिया सहित कुल 7 जिले पूरी तरह कवर कर लिए जाएंगे। शेष जिले वर्ष 2023 तक पूर्ण कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के 34 हजार 305 गाँवों में सतही स्नोट आधारित समूह योजनाओं से नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेष 16 हजार 382 गाँवों में ट्रेटो फिटिंग द्वारा सुविधा का विस्तार किया जाना है। प्रदेश में 32 लाख 41 हजार परिवारों तक योजना का विस्तार किया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में 25 लाख से अधिक एफएचटीसी के लक्ष्यों वाले राज्यों में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया।

2021

आगामी कॉन्फ्रेंस में अब कुपोषण और जल संरक्षण की समीक्षा करेंगे सीएम

धोपाल, (प्रस)। प्रदेश में कुपोषण में कितने पीसटी कमी आई और इसके लिए विभाग ने क्या रणनीति अपनाई है, इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक मार्च को होने वाली कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इसके अलावा जल संरक्षण की भी समीक्षा करेंगे।

जानकारी के अनुसार एक मार्च को होने वाली में कॉन्फ्रेंस में कुपोषण से मुक्ति के अपनाई गई रणनीति के क्रियान्वयन और आगनबाइयों में पोषण आहार एवं पूरक पोषण आहार के वितरण की प्रमुखता से समीक्षा होगी। विभागों ने इसकी तैयारी

शुरू कर दी है। इसके अलावा आठ फरवरी को हुई कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन, माफिया के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, ग्रीष्म ऋतु में जल संरक्षण एवं प्रबंधन, कानून व्यवस्था की स्थिति, फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर चर्चा, गेहूँ उत्पादन, मैदानी अमले की फील्ड में उपस्थिति के संबंध में प्रस्तावित योजना पर चर्चा, सरकारी जमीन पर होने वाले अतिक्रमण की पहचान के संबंध में प्रस्तुतिकरण और सीएम हेल्पलाइन को विशेष टूल के रूप में उपयोग करने के विषय में प्रस्तुतिकरण होगा।

जीपीएस से रखी जा रही है निगरानी

रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण वाहन के माध्यम से घर-घर से कचरा संग्रहण किया जा रहा है इस कार्य में और गति लाये जाने हेतु कचरा संग्रहण वाहनों पर जीपीएस सिस्टम से निगरानी रखी जा रही है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु वाहन वाडों में समय पर पहुंचे व तप रूट पर चले इस हेतु वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। सिविक सेन्टर स्थित मिटिंग हॉल में संचालित एस्बीएम सेल से वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है। वाहन वाडों में समय पर नहीं पहुंचने पर संबंधित ड्राइवर व कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी।

नई गाइडलाइन की तैयारी • 2019-20 की गाइडलाइन में 20% कम किए थे जमीन के भाव, वर्ष 2020-21 में कोरोना के चलते नहीं बढ़ाए थे जिन क्षेत्रों में बाजार मूल्य ज्यादा, वहां महंगी होगी जमीन

विशेष संवाददाता | रतलाम

1 अक्टूबर से जमीनों के भाव नए सिरे से तय करने के लिए गाइडलाइन को तैयारी शुरू हो गई है। इस बार की गाइडलाइन में इन इलाकों में जमीनों के दाम बढ़ाने की तैयारी है। जिन इलाकों में गाइडलाइन से ज्यादा भाव में जमीनों के खरीद हो रहे हैं। इससे इन इलाकों में गाइडलाइन 25% तक बढ़ाने का है। नई गाइडलाइन को लेकर जिला पंचायत विभाग के कम सिक्यूरिटी इनफोर्मेशन की जानकारी निकाल रहे हैं जिन इलाकों में खरीदों के खरीद गाइडलाइन से ज्यादा दाम में हुए हैं। इसी फीसिलिटी का फायदा कर प्रस्ताव में शामिल किया जा रहा है। इससे बाद इन इलाकों में दाम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद उप मुख्यालय समिति में इन इलाकों को रखना जाएगा। यहां से जिला मुख्यालय समिति को बैठक में प्रस्ताव रखे जाएंगे। समिति को सुझाव देने के बाद इसे कमीशन के लिए सार्वजनिक धारणापत्र भेजा जाएगा जहाँ का विचारण वर्ष 1 अक्टूबर से नई गाइडलाइन लागू हो सके।



गाइडलाइन कम होने के ये नुकसान

बाजार की तुलना में गाइडलाइन कम होने से जमीन नुकसान खरीदारों का है क्योंकि बाजार की कीमतों में फ्लॉट के ₹ 2000 से 4000 रुपए के बीच है लेकिन गाइडलाइन 500 रुपए के आसपास हो है। राष्ट्रीयकृत बैंक गाइडलाइन के हिसाब में 80 से 90% फाइनेंस करते हैं। ऐसे में जमीन खरीदने में आसानी नहीं आती खरीदने का समय भी लगने में ही जा रहा है।



ऐसे में स्थिति को दायरों में एंजॉर करके या फाइनेंस कंपनियों के पास लूकवान पड़ता है। वे बाजार मूल्य पर भी लूकवान कर देते हैं लेकिन बाजार दाम 16 से 24% तक है। इससे लोगों को दायरों में जम्मा दाम लूकवान पड़ रहा है।

ऐसे तैयार की जाती हैं गाइडलाइनें
प्रस्तावित गाइडलाइन जिला पंचायत विभाग के कम सिक्यूरिटी तैयार करते हैं। वे प्रस्ताव में रात में हुए जमीनों के खरीदों को लूकवाने जतन है कि जिन इलाकों में खरीदें खरीद हुए और किंग बंधन पर हुए। इस आधार पर गाइडलाइन प्रस्तावित की जाती है। जहाँ जमीनों की ज्यादा डिमांड है और भाव ज्यादा है। जहाँ के दाम ज्यादा बढ़ाने जाते हैं।

दो साल पहले कम की थी गाइडलाइन
दो साल पहले यानी वर्ष 2019-20 की बात करें तो गाइडलाइन की पर 20 फीसदी कम थी। इससे खरीद और बंधन खरीदारों का दाम था। खरीदने वाले यानी 2020-21 में कोरोना के चलते गाइडलाइन नहीं बढ़ी थी। ऐसे में 2021-22 की गाइडलाइन में दाम बढ़ाने का है।

जानकार ये बोलें

- 2% निगम इव्यूटि जनवरी में बढ़ी थी अब गाइडलाइन नहीं बढ़ाना चाहिए
- एक जमीनी में स्टॉक इव्यूटि 10.50% से बढ़कर 12.50% हो गई है। इससे हजार बंधन खरीद की सिक्यूरिटी पर 20 हजार बंधन ज्यादा लग रहे हैं। यदि गाइडलाइन बढ़ी तो लोग खरीदों में दूर हो सकते हैं। इसीलिए यह नहीं बढ़ाना चाहिए।
- नियंत्रण समिति, पूर्व अध्यक्ष जयदेव शंकरदास शर्मा और जयदेव शर्मा के अनुसार
- अभी प्राथमिक तैयारी चल रही है
- गाइडलाइन में लागू होने में कुछ सुधार का समय है। इससे नियंत्रण समिति तैयारी चल रही है जिससे जमीन खरीद रहे हैं। गाइडलाइन को लेकर कुछ नहीं बोलना चाहिए है।
- प्रस्तावित गाइडलाइन, जयदेव शर्मा



नगर पालिकाओं, पंचायतों की मतदाता सूची पर दावे आपत्ति 15 फरवरी तक लिए जाएंगे निर्वाचन के संदर्भ में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

रतलाम। आगामी नगर पालिका एवं पंचायतों के निर्वाचन के संदर्भ में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति 15 फरवरी तक लिए जा रहे हैं। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपालचंद्र डांड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम राहुल धोटे, अभिषेक गहलोत, श्रीमती कामिनी ठाकुर, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि दिनेश शर्मा, अभय जैन, पीयूष बाफना, समरथ चौहान, एम.एल. नगावत तथा जिले के तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर गोपालचंद्र डांड ने बताया कि प्रारूप मतदाता

सूची पर दावे आपत्ति प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा निर्धारित दावा आपत्ति केंद्रों पर प्राप्त करना आरंभ कर दिए गए हैं, जो आगामी 15 फरवरी की दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।

आयोग द्वारा दावा आपत्ति के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्रों के प्रारूप में परिवर्तन कर नए प्रारूप ईआर-1 परिवर्धन हेतु, ईआर-2 विलोपन हेतु तथा ईआर-3 संशोधन के लिए जारी किए गए हैं। यह सभी आवेदन पत्र प्राधिकृत कर्मचारी के पास उपलब्ध रहेंगे।

कलेक्टर ने बताया कि दावा आपत्ति लेने के लिए बूथ लेवल अधिकारी अपने निर्धारित बूथ पर प्रातः 10.30 से शाम 5.30 बजे तक प्राप्त करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि जो भी बीएलओ अपनी ड्यूटी में कोताही बरतेंगे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

27 फरवरी को वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी फोटो रहित मतदाता सूची

रतलाम। आगामी नगर पालिका एवं पंचायतों के निर्वाचन को लेकर सोमवार शाम जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में हुई। निराकरण के बाद 27 फरवरी को वेबसाइट पर फोटो रहित मतदाता सूची अपलोड होगी। 23 फरवरी को निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ईआरएमएस में प्रविष्टि होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी गोपालचंद्र डांड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर जमुना भिड़े आदि अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बताया कि दावा आपत्ति लेने के लिए बूथ लेवल के अधिकारी सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक मौजूद रहेंगे। इनमें से जो बीएलओ ड्यूटी में कोताही बरतेंगे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जाएगा

प्रसारण न्यूज • रतलाम

नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डांड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया

गया तथा 08 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 643 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गोशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 08 फरवरी को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलकापुरी, ग्लोबस कालोनी, नयागांव, राम मंदिर से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये। शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़कों चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़े का निर्माण कर

मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी। नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, ज्ञान प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

110 दिनों में ठीक किए 142 वॉल्व व 727 पाइप लीकेज

रतलाम। शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पाइप लाइन व वॉल्व लीकेज ठीक करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 65 दिनों में 103 वॉल्व व 466 पाइप लाइन लीकेजों को ठीक किया जा चुका है। रतलाम क्लराफिा अभियान कंट्रोल ग्रुप में लीकेज की समस्या को अप्लोड कर तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है। मंगलवार को अलकापुरी वी-68 के सामने, मुखर्जी नगर, हरमाला रोड ताज स्टोन के पास, गांधी नगर, सेंट जोसेफ बॉयन्ट स्कूल के पास, फुरोहित का वास, समता परिसर, बीहरा बाखल व मिशन कम्पाउंड में पाइप लाइन लीकेज के साथ कस्तूरबा नगर टेंकी का एयर वॉल्व ठीक किया गया। उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री सुहास पंडित, भैयालाल चौधरी के अलावा नीरज यादव, मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

649 मवेशियों को पकड़कर गोशालाओं में भेजा

रतलाम। नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गोशालाओं में भेजा जा रहा है। इसके तहत अब तक 649 मवेशियों को पकड़कर जिले की विभिन्न गोशालाओं में भेजा जा चुका है। मंगलवार को हनुमान ताल, अलकापुरी, सन्तपुरी, मुखर्जी नगर व कस्तूरबा नगर से उक्त मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गए।

दरोगा व सफाई कर्मचारी का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम। धनजी भाई के नेहरे में सफाई उपरंत कचरा नहीं उठाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दरोगा दिनेश-मोतीलाल व सफाई संरक्षक रानीबाई-विनोद का एक दिवस का वेतन काटा जाकर में कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। दोनों से तीन दिवस में स्पष्टीकरण चलाया गया है।

निकाय चुनाव से पहले निगम, मंडलों में सरकार करेगी नियुक्तियां

भोपाल, (प्रसं)। नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले सरकार निगम मंडलों में नियुक्तियां करने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे का कारण निकाय चुनाव में टिकट के बाद पैदा होने वाले असंतोष को दबाना है। कुछ दमदार नेताओं को निगम और मंडलों में नियुक्त करने के बाद

निकाय चुनाव में उनकी दायेंदारी समाप्त हो जाएगी जिससे भाजपा को उम्मीदवार चयन में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

22 मार्च 2020 के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के कुछ दिन बाद से निगम-मंडलों में नियुक्तियों की चर्चा शुरू हो गई थी,

लेकिन सरकार और संगठन उपचुनाव का हवाला देते इस मामले को टाल दिया था। नवंबर 2020 में उपचुनाव में भाजपा ने विजय प्राप्त कर सरकार का

**कई नेताओं को
संतुष्ट करने
संगठन भी कर
रहा तैयारी**

स्थिर कर दिया उसके बाद भी सरकार ने निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं की गईं। बीजेपी विधायकों और नेताओं ने सरकार

और संगठन के समक्ष कर वा अपनी बात रखी, लेकिन हर वा नियुक्तियों को कुछ न कुछ कारण बताकर टाल दी गईं। अब जबकि निकाय चुनाव में बीजेपी को अपना प्रदर्शन बेहतर रखना है, इसलिए निकाय चुनाव से पहले वा नियुक्तियां की जा सकती है।

2/6 निगम महापौर टिकट दावेदारों की भी होगी नियुक्तियां

प्रदेश की नगर निगम महापौर के कई दावेदार होने से बीजेपी के आला नेताओं की परेशानी लगातार बढ़ रही है। संगठन निकाय चुनाव से पहले किसी भी बड़े नेता को नराज नहीं करना चाहता है, इसलिए कई नेताओं को निगम और मंडल में पद दिया जा सकता है। इसी तरह कई विधायकों को भी पद देने की तैयारी है। संगठन में इतकी तैयारी शुरू हो गई है अगली दिनों में ऐसे नेताओं की सूची तैयार हो जाएगी जिन्हें निगम मंडलों में पद देना है हालांकि सूची में कई नाम शामिल होंगे। इसमें से सरकार, संगठन और बड़े नेताओं का पसंद से नियुक्तियां दी जाएगी।

सिंधिया खेमे के विधायकों को इंतजार

उपचुनाव के बाद सिंधिया खेमे के विधायकों को मंत्री बनने की आस थी, लेकिन सिर्फ व विधायक तुलसीराम मिलाहट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई अन्य विधायकों के हिस्से में इंतजार आया। वार माह से आस लगाए विधायकों को अब निगम मंडल में पद देकर संतुष्ट किया जाएगा। इस क्रम में विधानसभा हारने वाली इमरती देवी भी शामिल है।

कांग्रेस सरकार ने निरस्त की थी निगम मंडल नियुक्तियां

दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार बनी थी, सरकार बनते ही खर्च को कम करने के लिए निगम-मंडलों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गई थी। जबकि कांग्रेस की सरकार रही तब तक निगम मंडल में पॉलीटिकल नियुक्तियों के रास्ते बंद रहे।

निजी एजेंसियां को सौंपी सर्वे की जिम्मेदारी : अभी कई सड़कों की हालत दयनीय फोरलेन होंगी प्रदेश की 12 से ज्यादा सड़कें, सफर करने पर चुकाने होंगे पैसे



पत्रिका
इंटेण्ड
स्टोरी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल प्रदेश की 12 से ज्यादा सड़कों को फोरलेन करने की तैयारी है। फिजिबिलिटी सर्वे का काम निजी एजेंसियों को दिया गया है। एजेंसियां 6 माह के अंदर रिपोर्ट मप्र रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंपेंगी। इसके आधार पर सड़कों को टू-लेन से लेकर फोरलेन किया जाएगा। सर्वे में देखा जा रहा है कि इन सड़कों पर वाहनों का कितना दबाव है। कितने बड़े वाहन गुजरते हैं। सरकार निर्माण वीओटी के तहत करेगी। ऐसे में टोल टैक्स वसूला जाएगा।

सरकार निर्माण और रखरखाव के लिए सड़कों को बनाने 20 से 25 साल के लिए निजी एजेंसियों को देगी। भोपाल-इंदौर सहित प्रदेश के 25 से 30 सड़कों में टोल से राशि वसूली जा रही है। हालांकि इन सड़कों का निर्माण पहले भी निजी एजेंसियों के जरिए किया गया था, जो इसकी वसूली टोल से कर रही थी, लेकिन डेढ़ से दो साल पहले उनका अनुबंध समाप्त हो गया था। अब सरकार इन सड़कों का चौड़ीकरण करने की तैयारी कर रही है। निर्माण में दो से तीन साल लगेंगे।

इन सड़कों का होना है चौड़ीकरण- हरदा-खंडवा, रायसेन-गैरलगांज-राहतगढ़, होशंगाबाद-पिपरिया, रतलाम-झाबुआ, हरदा से टिमरनी, रीवा-ब्यौहारी, ब्यौहारी-शाहडोल, शाहपुरा-नरसिंहपुर, सिवनी-बालाघाट, घोंसला-माहिवपुर, मलहरा-लौड़ी, चंदला-आजमगढ़, चंदला-महोबा, होशंगाबाद-हरदा-खंडवा।



ऐसा होगा सड़कों का नेटवर्क

शाहपुरा-भिटौनी से नरसिंहपुर सड़क फोरलेन में लक्ष्य होनी है। शाहपुरा-भिटौनी का अधिकांश हिस्सा जबलपुर जिले में है। यह मार्ग गोटेगांव होते हुए नरसिंहपुर जिले में दादा महाराज के पास से गुजरने वाले फोरलेन से जोड़ा जाएगा। गोटेगांव का करीब 35 किलोमीटर और जबलपुर जिले का शाहपुरा से लेकर

गोटेगांव तक का करीब 20 किलोमीटर का क्षेत्र फोरलेन में परिवर्तित किया जाएगा। वर्तमान में गोटेगांव से नरसिंहपुर तक एक लेन है। इसी को फोरलेन में परिवर्तित करने की योजना है, जो दादा महाराज के पास तक बनाई जाएगी। इसके बाद दादा महाराज के पास फोरलेन सिवनी से लेकर सागर वाले फोरलेन में जोड़ा जाएगा।

ग्राउंड रिपोर्ट

दोनों छोर से समझिए स्थिति



झाबुआ पत्रिका, रतलाम-झाबुआ मार्ग पर पुलिस का एक हिस्सा टूटा है। मिट्टी धसक गई है। रात के अंधेरे में गड़दे नजर नहीं आते। अचानक नजर आने पर पता चलता है कि गड़दे हैं। इससे हावसे की आशंका रहती है। यह मार्ग गुजरात को जोड़ता है। रतलाम होते हुए राजस्थान भी पहुंचा जा सकता है। वीआइपी लोग भी गुजरते हैं, फिर भी मेटेनैस नहीं हो रहा।

रतलाम झाबुआ मार्ग

रतलाम पत्रिका, जिले की सीमा में लगभग 27 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की हालत ऐसी है कि यह सिंगल रोड जैसा रह गया है। पूरा रास्ता सैकड़ों जगह से जर्जर है। निर्माण के बाद सिर्फ एक बार मेटेनैस हुआ है। इस सड़क को एमपीआरडीसी ने करीब 6 साल पहले बनाया था और उसके बाद तीन साल पहले छोटी-मोटी मरम्मत की गई थी।



नगर पालिकाओं, पंचायतों की मतदाता सूची पर दावे आपत्ति 15 फरवरी तक लिए जाएंगे

निर्वाचन के संदर्भ में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

रतलाम। आगामी नगर पालिका एवं पंचायतों के निर्वाचन के संदर्भ में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति 15 फरवरी तक लिए जा रहे हैं। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपालचंद्र डांड, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम श्री राहुल धोटे, श्री अभिषेक गहलोत, श्रीमती कामिनी ठाकुर, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि श्री दिनेश शर्मा, श्री अभय जैन, श्री पीयूष बाफना, श्री समरथ चौहान, श्री एम.एल.नगावत तथा विले के तहसीलदार उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डांड ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा निर्धारित दावा आपत्ति केंद्रों पर प्राप्त करना आरंभ कर दिए गए हैं, जो आगामी 15 फरवरी को

दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्रों के प्रारूप में परिवर्तन कर नए प्रारूप ईआर-1 परिवर्धन हेतु, ईआर-2 विलोपन हेतु तथा ईआर-3 संशोधन के लिए जारी किए गए हैं। यह सभी आवेदन पत्र प्राधिकृत कर्मचारी के पास उपलब्ध रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि दावा आपत्ति लेने के लिए बूथ लेवल अधिकारी अपने निर्धारित बूथ पर प्रातः 10:30 से शाम 5:30 बजे तक प्राप्त करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि जो भी बीएलओ अपनी इयूटी में कोताही बरतेंगे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बताया गया कि परिवर्तन दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई मतदाता अपने नाम सूची के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अंतरित करना चाहता है तो उसके

द्वारा भी इस प्रारूप में दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार विलोपन आपत्ति की जानकारी में बताया गया कि ऐसी आपत्ति केवल ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम संबंधित नगर पालिका या पंचायत की मतदाता सूची में पहले से ही सम्मिलित है, अर्थात् जो संबंधित नगर पालिका या पंचायत का मतदाता है संशोधन आपत्ति के तहत यह आपत्ति मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के धरि जैसे मकान नंबर, नाम, पिता, पति का नाम, आयु के संबंध में अशुद्धि या त्रुटि पर आपत्ति हो सकती है। ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे संबंधित प्रविष्टि है। इसके लिए किसी अन्य मतदाता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।



जिले के सभी नगरीय निकाय आगामी 5 वर्षों का रोडमैप बनाएँ

रतलाम। जिले के सभी नगरीय निकाय आगामी 5 वर्षों का रोडमैप बनाएँ इस संबंध में कलेक्टर गोपालचंद्र डांड ने एक बैठक लेकर निर्देश दिए। आयोजित बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर पालिका अधिकारी 1 सप्ताह में अपना रोडमैप संबंधित जनप्रतिनिधि से चर्चा करके तैयार करें, इसके बाद कलेक्टर द्वारा भी अवलोकन किया जाएगा। कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री डांड ने एनयूएलएल योजना के तहत स्वरोजगार कार्यक्रम, स्व सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गठित समूहों की स्थिति, आवृत्ति निधि, बैंक लिंकेज, मल्टी लिंकेज, पीएस स्वनिधि, समन्वय समिति 2011 का निष्पत्ति, निकायों के बैंक खातों का सुकियुक्त करण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बीएलसी अशवासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत 300 दिवस तथा 100 दिवस की लक्षित शिकायतों के निराकरण सहित राज्य स्तरीय ग्रेडिंग में निकायों को सुधार लाने के लिए भी निर्देशित किया गया। सीएमओ बड़ीदा तथा नाम्नी की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई साथ ही कलेक्टर द्वारा सभी निकायों को आगामी ग्रेडिंग में 'ए' ग्रेड प्राप्त करने के लिए मेहनत करने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना अधिकारी सहरी विकास निशिकांत शुक्ला, सीएमओ जावत श्रीमती नीता जैन, सीएमओ सैताना जेपी गुहा, सीएमओ आलोट सुश्री सोन्या सरयाम, सीएमओ पिपलोदा श्रीमती आरती गहवाल, सीएमओ बड़ीदा श्री धर्मचंद जैन, सीएमओ ताल श्री अशोक शर्मा, एपीओ श्री अरुण पाठक उपस्थित थे।

सभी निकाय 7 दिवस में 5 वर्षों का रोडमैप तैयार करें

रतलाम। जिले के सभी नगरीय निकाय आगामी 5 वर्षों का रोडमैप बनाएंगे, इस संबंध में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने एक बैठक लेकर निर्देश दिए। आयोजित बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर पालिका अधिकारी 1 सप्ताह में अपना रोडमैप संबंधित जनप्रतिनिधि से चर्चा करके तैयार करें, इसके बाद कलेक्टर अवलोकन करेंगे। कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री डाड ने एनयूएलएल योजना के तहत स्वरोजगार कार्यक्रम, स्व सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गठित समूहों की स्थिति, आवर्ती निधि, बैंक लिंकेज, मार्केट लिंकेज, पीएम स्वनिधि, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी, निकायों के बैंक खातों का युक्तियुक्त करण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना



अंतर्गत बीएलसी आवासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री रेलप्लाइन के तहत 300 दिवस तथा 100 दिवस की लंबित शिकायतों के निराकरण सहित राज्य स्तरीय प्रेडिंंग में निकायों को सुधार लाने के लिए भी निर्देशित किया गया। सीएमओ बड़ौदा तथा नामली की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई साथ ही कलेक्टर द्वारा सभी निकायों को आगामी प्रेडिंंग में 'ए'

ग्रेड प्राप्त करने के लिए मेहनत करने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना अधिकारी शहरी विकास निशिकांत शुक्ला, सीएमओ जावरा नीता जैन, सीएमओ सैलाना जेपी गुहा, सीएमओ आलोट संध्या सरयाम, सीएमओ पिपलीदा आरती गरवाल, सीएमओ बड़ौदा धर्मचंद जैन, सीएमओ ताल अशोक शर्मा, एपीओ अरुण पाठक उपस्थित थे।

नगरीय निकाय आगामी पांच वर्षों का रोडमैप बनाएंगे

रतलाम, जिले के सभी नगरीय निकाय आगामी 5 वर्षों का रोडमैप बनाएंगे, इस संबंध में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने मंगलवार को एक बैठक लेकर निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि नगर पालिका अधिकारी एक सप्ताह में अपना रोडमैप संबंधित जनप्रतिनिधि से चर्चा करके तैयार करें, इसके बाद कलेक्टर द्वारा भी अवलोकन किया जाएगा। कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर डाड ने एनयूएलएल योजना के तहत स्वरोजगार कार्यक्रम, स्व सहायता समूह के आर्थिक

सशक्तिकरण के लिए गठित समूहों की स्थिति, आवर्ती निधि, बैंक लिंकेज, मार्केट लिंकेज, पीएम स्वनिधि, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी, निकायों के बैंक खातों का युक्तियुक्त करण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बीएलसी आवासों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में परियोजना अधिकारी शहरी विकास निशिकांत शुक्ला, सीएमओ जावरा नीता जैन, सीएमओ सैलाना जेपी गुहा, सीएमओ आलोट संध्या सरयाम, सीएमओ पिपलीदा आरती गरवाल उपस्थित थे।

जिले के सभी नगरीय निकाय आगामी पांच वर्षों का रोडमैप बनाएं

रतलाम। जिले के सभी नगरीय निकाय आगामी पांच वर्षों का रोडमैप बनाएंगे। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने मंगलवार को बैठक में सभी सीएमओ को निर्देशित किया कि एक सप्ताह में रोडमैप संबंधित जनप्रतिनिधि से चर्चा करके तैयार करें।

कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने एनयूएलएल योजना के तहत स्वरोजगार कार्यक्रम, स्व सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गठित समूहों की स्थिति,

आवर्ती निधि, बैंक लिंकेज, मार्केट लिंकेज, पीएम स्वनिधि, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी, निकायों के बैंक खातों का युक्तियुक्त करण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बीएलसी आवासों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेलप्लाइन के तहत 300 तथा 100 दिवस की लंबित शिकायतों के निराकरण सहित राज्य स्तरीय प्रेडिंंग में निकायों को सुधार लाने के लिए भी निर्देशित किया गया।

सीएमओ बड़ौदा तथा नामली

की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। साथ ही कलेक्टर द्वारा सभी निकायों को आगामी प्रेडिंंग में 'ए' ग्रेड प्राप्त करने के लिए मेहनत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में परियोजना अधिकारी शहरी विकास निशिकांत शुक्ला, सीएमओ जावरा नीता जैन, सीएमओ सैलाना जेपी गुहा, सीएमओ आलोट संध्या सरयाम, सीएमओ पिपलीदा आरती गरवाल, सीएमओ बड़ौदा धर्मचंद जैन, सीएमओ ताल अशोक शर्मा, एपीओ अरुण पाठक उपस्थित थे।

सभी नगरीय निकायों का पांच साल के विकास कार्यों का रोडमैप बनेगा

भास्कर संवाददाता | रतलाम

नगर निगम रतलाम की तरह अब जिले के सभी नगरीय निकायों का पांच साल में किए जाने वाले विकास कार्यों का रोडमैप बनेगा। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने इस संबंध में सभी निकायों के अधिकारियों को निर्देश देकर एक सप्ताह में जनप्रतिनिधि से चर्चा कर रोडमैप तैयार करने को कहा है।

कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर ने एनयूएलएल, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्व सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गठित समूहों की स्थिति, आवर्ती निधि, बैंक लिंकेज, मार्केट लिंकेज, पीएम स्वनिधि, स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी, निकायों के बैंक खातों का युक्तियुक्त करण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बीएलसी आवासों की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना अधिकारी शहरी विकास निशिकांत शुक्ला, सीएमओ जावरा नीता जैन, सीएमओ सैलाना जेपी गुहा, सीएमओ आलोट संध्या सरयाम, सीएमओ पिपलीदा आरती गरवाल, सीएमओ बड़ौदा धर्मचंद जैन, सीएमओ ताल अशोक शर्मा, एपीओ अरुण पाठक उपस्थित रहे।

भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक चेतन्य काश्यप का अभिनंदन

रतलाम को नगर से महानगर बनाने की दिशा में किए विकास कार्यों से उत्साहित

रतलाम ■ राज नूज नेटवर्क

भाजपा की मंडल इकाइयों एवं वार्ड कार्यकर्ताओं ने रतलाम में म.प्र. का दूसरा सबसे बड़ा 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में 1800 करोड़ की लागत का निवेश क्षेत्र स्वीकृत करने एवं अग्राध्यक्ष श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये समर्पित करने पर विधायक चेतन्य काश्यप का अभिनंदन किया। अभिनंदन समारोह महामण्डलेश्वर श्री विदम्बरानन्द सरस्वतीजी महाराज के सानिध्य में हुआ। इसमें विधायक श्री काश्यप ने रतलाम के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प व्यक्त किया। अभिनंदन समारोह में भाजपा मण्डल अध्यक्ष नितेश माधो, मन्सूर पुरोहित, कल्याणवीर खड्गवाला, कृष्ण कुमार सोनी एवं अदित्य डागा ने श्री काश्यप को साभार फलजकार एवं शाल ओटाकर सम्मानित किया। उन्हें इस मौके पर अभिनंदन पत्र भी भेंट किया। समारोह में सभी मंडलों के पदाधिकारियों एवं वार्ड कार्यकर्ताओं ने अनुसूचन पूर्वक श्री काश्यप के प्रश्नों से हो रहे रतलाम के विकास का सम्मान किया। इससे पूर्व पांचों मंडल अध्यक्ष ने समारोह को संबोधित कर विधायक श्री काश्यप द्वारा शहर के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। समारोह के अंश में कार्यकर्ताओं के समक्ष आगामी पांच सालों में होने वाले विकास कार्यों का प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत हुआ।

इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कन्देवालाल मौर्य, बजरंग पुरोहित, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्यक्ष, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, पूर्व निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, दिनेश शर्मा, बन्दीलाल पारिस, जिला मोडिया प्रमारी अरुण राव, सुग्री झोपटी प्रकोष्ठ की सह संयोजक अनिता कटारिया, आई.टी. प्रकोष्ठ के सह



सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र - मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान

संयोजक सोमेश पालीवाल, समाजसेवी मोहनलाल भट्ट सहित पार्टी व मोर्चा, प्रकोष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। अभिनंदन समारोह का संचालन जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा ने किया।

रतलाम की मालवा का प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र बनाएँगे-काश्यप: अभिनंदन समारोह में विधायक चेतन्य काश्यप ने कहा कि रतलाम की जनता ने दो बार विधायक चुनकर उन्हें जो दायित्व सौंपा था इसकी पूर्ति में वे कभी पीछे नहीं रहेंगे। यह सम्मान उनका नहीं उस दायित्व का ही सम्मान है वे तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। श्री काश्यप ने कहा कि

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का दौरा इस बार हर मायने में अलग रहा है। नगर निगम आगामी पांच वर्षों में शहर को क्या देगा इसका प्रजेंटेशन उन्होंने देखा और शासन की तरफ से होने वाले कार्यों को आगे बढ़ाया। रतलाम में 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में 1800 करोड़ की लागत से जो नया निवेश क्षेत्र बनेगा वह रतलाम की वर्तमान भौगोलिक आकार से दूगना होगा। केंद्र सरकार द्वारा देश में 7 बड़े निवेश क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। जहाँ 1-1 हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। म.प्र. सरकार ने रतलाम को इस कार्य के लिए चुन लिया है। श्री काश्यप ने शहर में सड़कों के नव

विधायक के प्रति जनता का ऐसा लगाव कहीं नहीं देखा: विदम्बरानंदजी

अभिनंदन समारोह में महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विदम्बरानंद सरस्वतीजी म.स. ने आशीर्षकन में कहा कि वे कई वर्षों से रतलाम में आ रहे हैं और देश भर में कई स्थानों पर जाते हैं, लेकिन विधायक के प्रति जनता का ऐसा लगाव कहीं नहीं देखा। शहर विधायक चेतन्य काश्यप को जनता ने जो दायित्व सौंपा है। उसका वे बखूबी निर्वहण कर रहे हैं। इतने कम समय में रतलाम को बदलने की जो कोशिश उन्होंने की है वह किसी विधायक ने नहीं की होगी। स्वामीजी ने कहा कि कर्म के प्रति निष्ठा और दायित्व निर्वहण करते हुए शहर में उन्हें ही व्यक्तिगत नजर आए जिनमें पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बदल दिया है, दूसरे व्यक्ति रतलाम विधायक श्री काश्यप है जिन्होंने शहर की सड़कें बदल दी है। विकास के साथ आस्था की भी श्री काश्यप में गहरी पैठ है। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये का समर्पण इसका प्रमाण है।

निर्माण, मेडिकल कॉलेज के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण, गरीबों के आवास, सुग्री मुक्त रतलाम के प्रयास और व्यापार वृद्धि की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक विकसित और युवाओं के भविष्य का रतलाम बनाने के लिए वे संकल्पित हैं। रतलाम को मालवा का प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र बनाएँगे, जिससे उसे पुराना वैभव पुनः प्राप्त होगा।

मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौकलों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाडव निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 08 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 643 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गोशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 08 फरवरी को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलकापुरी, ब्लोबस कालोनी, नयागांव, राम मंदिर से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये। शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौकलों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं लबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है।

इन्दौर

सफाई को जीवन का हिस्सा बनाया तो कम हुआ मलेरिया

स्वास्थ्य • कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बीच अच्छी आदत अपनाने से बीमारी पर पाया नियंत्रण

रत्नलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में कोरोनाकाल में जहां लोगों को कई तरह की परेशानी हुई, वहीं कुछ अच्छा असर भी सामने आया है। कोविड की चुनौतियों के बीच लोगों ने अपनी आदतों को बदला और साफ-सफाई को ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाया। जिला प्रशासन की देखरेख में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाए। लॉकडाउन में शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता की गतिविधियां चली। इसके चलते जिले में इस साल दो महीने में मलेरिया का एक भी मरीज नहीं मिला। अगर ऐसे ही साफ-सफाई से लोग जुड़े रहे तो अन्य बीमारियों के साथ जल्द ही मलेरिया से भी जिला मुक्त हो जाएगा।



जिले में 2019 में मलेरिया के 269 मरीज मिले थे। साल 2020 में 180 केस सामने आए थे, जबकि साल 2021 के दो महीनों में एक भी मरीज नहीं मिला। आठ साल में मलेरिया से एक भी मौत भी नहीं हुई है।

जिले में आठ साल में इस तरह रही मलेरिया के मरीजों की स्थिति			
साल	पीछी केस	पीएफ केस	कुल केस
2014	1531	1019	2540
2015	2824	942	3366
2016	1289	586	1875
2017	806	241	1047
2018	484	176	660
2019	211	58	269
2020	88	20	108

मौत एनोफिलिस मच्छर की संख्या में कमी आई है। निकाश ने स्वच्छता अभियान और मलेरिया विभाग ने अपनी गतिविधियों को कोविड काल में भी चालू रखा जिससे मलेरिया पर अंकुश लगा है। लोगों ने साफाई को ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। इससे मलेरिया के नए मरीजों कम मिले हैं।
-डा. प्रदीप प्रसाद, जिला मलेरिया अधिकारी रत्नलाम

2020 में जांच व नए मरीज की संख्या			
सीएससी	जनसंख्या	कुल जांच	पॉजिटिव
बाजना	184199	2921	29
सेलम	136065	23681	18
बिलथाक	383067	41927	5
पिपलीवा	166007	23324	24
डॉईयागौवल	282512	30684	7
खारवाकला	246130	30940	9
रत्नलाम शहर	391706	31664	16
कुल	1709706	205141	108

स्वस्थ आदतों के साथ जीने लगे

स्वच्छता सबरो अहम
कोविड के बाद से लोगों के लिए स्वच्छता सबसे अहम है। घर के अंदर सफाई के सब रो बाहर भी अभियान चलाए जाते हैं। लोग खुद सेहत के प्रति भी सजग हो गए हैं।

मास्क ज़िंदगी
अव्यक्त लेंगे तो ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। जो संगमन के साथ ही अन्य बीमारियों से बचता है।

हाथ धोना आदत में
सबसे जल्दरी हाथ धोना लोगों की आदत में शामिल हो गया है। लॉक डाउन से भी लगातार हाथों की सफाई को लेकर सजग है। सैनिटाइजर से भी असर पड़ा है।

नईदुनिया